सर्वहारा दृष्टिकोण

डिजिटल संस्करण
इंटरनेट के जरिये वितरण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) SUCI (C) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-40 अंक 21 | 7 से 21 नवम्बर 2025 | मुख्य संपादकः कॉमरेड प्रभास घोष | कुल पृष्ठ : 8 | मूल्य : 4 रुपये | पृष्ठ 1

महान नवम्बर क्रांति जिन्दाबाद

"समाजवाद का अर्थ है वर्गों का उन्मूलन। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व ने वर्गों को खत्म करने के लिए वह सब कुछ किया है, जो वह कर सकता था। पर वर्गों को यकायक खत्म नहीं किया जा सकता। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के युग में वर्ग अभी भी बाकी हैं और बाकी रहेंगे। जब वर्ग मिट जायेंगे, तब अधिनायकत्व अनावश्यक हो जायेगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के बिना वे नहीं मिटेंगे। वर्ग बाकी तो रह गये हैं, पर सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के युग में हर वर्ग में एक परिवर्तन आया है और वर्गों के पारस्परिक संबंध भी बदल गये हैं। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के तहत वर्ग संघर्ष का लोप नहीं होता; वह केवल दूसरा रूप अपना लेता है।"

– लेनिन (सर्वहारा वर्ग अधिनायकत्व के युग की अर्थनीति और राजनीति)

"अतीत में क्रांतियों का अंत आमतौर पर शोषकों के एक समूह को सरकारी गद्दी से हटाकर उसकी जगह शोषकों के दूसरे समूह को बिठा देने में हुआ था। शोषक बदले, पर शोषण कायम रहा। ... अक्टूबर क्रांति इन क्रांतियों से सैद्धांतिक रूप से अलग है। इसका उद्देश्य एक प्रकार के शोषण की जगह दूसरे प्रकार का शोषण लाना नहीं है, शोषकों के एक समूह की जगह शोषकों के एक दूसरे समूह को प्रतिस्थापित करना नहीं है, बल्कि मनुष्य द्वारा मनुष्य के हर प्रकार के शोषण को समाप्त करना है।"

–स्तालिन (अक्टूबर क्रांति का अंतर्राष्ट्रीय चरित्र, दसवीं वर्षगांठ के अवसर पर)

"सोवियत संघ अजेय रहा है, क्योंकि यह एक ऐसा देश है, जिसमें समाजवादी व्यवस्था ने पूंजीवादी व्यवस्था की जगह ले ली है और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व ने शोषणकारी वर्गों की तानाशाही की जगह ले ली है–एक ऐसा देश, जो अपनी सामाजिक उत्पादिका शक्तियों को इतनी तेज रफ्तार से विकसित करता है कि उस रफ्तार से पूंजीवादी देश ऐसा करने में असमर्थ हैं–और एक ऐसा देश है, जो वास्तव में सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयता का पालन करता है, वास्तव में राष्ट्रीय उत्पीड़न का विरोध करता है और उत्पीड़ित राष्ट्रों को खुद को मुक्त करने में मदद करता है। ऐसे देश को अपने खुद के तमाम अवाम और दुनिया के सभी देशों के अवाम का उत्साहपूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। सोवियत संघ को इन दोनों प्रकार का समर्थन प्राप्त है, जो राष्ट्रों के इतिहास में एक हद तक बेमिसाल है।"

– माओ त्से-तुंग (मास्को उत्सव सभा में भाषण, 6 नवंबर, 1957)

"नवंबर क्रांति ने दिखा दिया है कि मजदूर वर्ग क्रांति करने में सक्षम है। इस क्रांति ने निर्णायक रूप से सिद्ध कर दिया है कि विश्व बुर्जुआ लोकतांत्रिक क्रांति का युग समाप्त हो गया है और विश्व पूंजीवाद पतन के चरण में प्रवेश कर गया है, मरणासन्न हो गया है, यह प्रगति, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतंत्र का विरोधी है... इस प्रकार, सभी पहलुओं से, पूंजीवाद पतनशील है और प्रगति के विरुद्ध है। इसलिए इसे क्रांति की शक्ति से उखाड़ फेंकना होगा। निस्संदेह, सर्वहारा वर्ग ही इस क्रांति का नेतृत्व करेगा।"

– शिवदास घोष (चुनिंदा रचनाएं)

शोषण को और क्रूर बनाने के लिए श्रम कानूनों में बदलाव कर रही हैं सरकारें

केंद्र की मोदी सरकार पहले ही 29 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में बदल चुकी है। इस बार राज्य सरकारें भी अपने-अपने तरीके से श्रम कानूनों में बदलाव कर रही हैं। हाल ही में गुजरात की भाजपा सरकार ने विधानसभा में कानून पारित कर कारखानों में 12 घंटे का कार्य दिवस लागू किया। इसी तरह, महाराष्ट्र सरकार भी 12 घंटे का कार्य दिवस लागू करने जा रही है। देखा जा रहा है कि ज्यादातर भाजपा शासित राज्यों ने कार्य दिवस को 12 घंटे करने के लिए या तो कानून पारित कर दिया है या अध्यादेश जारी कर दिया है या करने वाले हैं। कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कांग्रेस शासित राज्य भी इस मामले पर विचार कर रहे हैं। तमिलनाडु में तो कारखाना अधिनियम में संशोधन कर उसे 12 घंटे कर दिया गया है। हालांकि कई राज्यों ने अभी तक इस पर कोई कानून पारित नहीं किया है, लेकिन हकीकत में, नियोक्ता यानी मालिक मनमाने घंटों तक काम करने के लिए मजदूर-कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं।

सन 1886 में अमेरिका के शिकागो शहर के हे मार्केट में 8 घंटे के काम की मांग को लेकर मजदूरों ने ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी। बहुत सारे मजदूर इस आंदोलन में मारे गए थे और चार मजदूर नेताओं की फांसी हो गई थी। यह आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया था। अंततः, 8 घंटे के कार्य दिवस को पूरी दुनिया में सरकारी मान्यता मिली। भारत में भी केंद्र और राज्य सरकारों ने 8 घंटे के कार्य दिवस को कानूनी मान्यता दे दी। इससे यह स्वीकार किया गया कि श्रमिकों को 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन की भी जरूरत है, क्योंकि उन्हें भी इंसानों की तरह जीने का अधिकार है। आजादी के लगभग आठ दशक बाद 8 घंटे की जगह 12 घंटे का कार्य दिवस लागू करके सरकारें श्रमिकों को आजादी-पूर्व के अमानवीय जीवन की ओर वापस ले जाने वाली हैं। भाजपा शासित राज्यों ने इस मजदूर-विरोधी रास्ते पर आगे कदम बढ़ाया है। कांग्रेस शासित राज्य और अन्य राज्य भी उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं।

देश के नियोक्ता यानी मालिक

(शेष पृष्ठ 2 पर)

एक निर्माण मजदूर की नजरों में सोवियत संघ

–मैं एक निर्माण मजदूर हूं। ...

अगस्त 1991 से पहले, हम एक और देश में रहते थे और उसके बाद हम दूसरे देश के बासिंदे हो गये। उस अगस्त से पहले हमारे देश को सोवियत संघ कहा जाता था।

मैं कौन हूं? मैं उन बेवकूफों में से एक हूं, जिन्होंने येल्तसिन का समर्थन किया था। मैं (रूस के) व्हाइट हाउस के सामने खड़ा होकर विरोध कर रहा था, एक टैंक के सामने लेटने को तैयार। तब सड़कें जन सैलाब में तब्दील हो गयी थीं, उफनती लहरों के शिखर पर लोगों के सिर ही सिर नजर आ रहे थे, जो सड़कों पर उतर आये थे। वे लहरें उमड़-घुमड़ रही थीं। लेकिन वे वहां आजादी के लिए मौत को गले लगाने के लिए तैयार थे, पूंजीवाद के लिए नहीं। मैं खुद को एक ऐसा इन्सान मानता हूं, जो ठगा गया। हमने वह पूंजीवाद नहीं चाहा था, जिसको गलत रास्ते की ओर हमें ले जाकर उन्होंने हमारे ऊपर थोप दिया है। नहीं, ... किसी भी रूप में नहीं, ... न तो अमेरिकी मॉडल में और न ही स्वीडिश मॉडल, किसी भी मॉडल में पूंजीवाद की हमें जरूरत नहीं है। मैंने किसी और की संपत्ति हड़पने के लिए विद्रोह शुरू नहीं किया था। हमने पुकारा था, "यूएसएसआर!" की बजाय "रूस!" चाहिए। मुझे अफसोस है कि उन्होंने हमें पानी की बौछारों से तितर-बितर क्यों नहीं किया और चौक पर कुछ मशीनगनें क्यों नहीं चलायीं। उन्हें दो-तीन सौ लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था और बाकी लोग तो ऐसे ही लुक-छिप जाते।

वे लोग आज कहां हैं, जिन्होंने हमें उस दिन सड़कों पर उतारा था? वे, जो कहते थे, "क्रेमलिन माफिया मुर्दाबाद!", "कल का दिन आजादी का!" आज उनके पास हमसे कहने

(शेष पृष्ठ 6 पर)

केरल में आशा कार्यकर्ताओं पर क्रूर हमला

केरल के तिरुवनंतपुरम में क्लिफ हाउस तक कूच कर रही आशा कार्यकर्ताओं और उनकी नेताओं पर पुलिस द्वारा बर्बर अत्याचार

केरल में आशा कार्यकर्ता 250 से ज्यादा दिनों से 21,000 रुपये मासिक वेतन की मांग को लेकर संघर्ष कर रही हैं। उन्होंने भूख हड़ताल की, अपने बाल कटवाए, रैलियां निकालीं और अपना आंदोलन जारी रखा। आशा कार्यकर्ताओं ने पिछले 22 अक्तूबर को 'मुख्यमंत्री आवास तक कूच' का आह्वान किया था। लेकिन सीपीआई (एम) नीत एलडीएफ सरकार की पुलिस ने न केवल रैली को रोकने की कोशिश की, बल्कि कार्यकर्ताओं, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, को भी बेरहमी से पीटा। उन्हें और आशा कार्यकर्ता आंदोलन की नेता कॉमरेड एस मिनी को घसीटकर जेल की गाड़ी में डाल दिया गया। जब बाकी कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए, तो पुलिस ने उन्हें पुलिस की गाड़ी से कुचलने की कोशिश की। यहां तक कि उन पर पानी की बौछारें भी की गईं। इससे केरल सरकार का निरंकुश चरित्र फिर से उजागर हुआ।

स्कूलों में आरएसएस की 'राष्ट्रनीति' की शुरुआत के खिलाफ

शिक्षा सम्मेलन आयोजित

नई दिल्ली : स्कूलों में आरएसएस की 'राष्ट्रनीति' की शुरुआत के खिलाफ एक शिक्षा सम्मेलन 16 अक्तूबर को यहां डॉ. एस. सत्यानंदन कॉन्फ्रेंस हॉल, वाईएमसीए में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन दो सत्रों में हुआ।

बुद्धिजीवियों के साथ पहले सत्र को एयूडी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजन कृष्ण और डीयू के दयाल सिंह कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. सचिन एन. ने संबोधित किया। सत्र की शुरुआत पाठ्यपुस्तकों में आरएसएस- 'राष्ट्रनीति' की शुरुआत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने के साथ हुई, जिसे जेएनयू छात्र और एआईडीएसओ, दिल्ली राज्य कार्यालय सचिव कॉमरेड राहुल सिंह ने पढ़ा।

अगला सत्र वामपंथी और लोकतांत्रिक छात्र संगठनों को लेकर था। आइसा के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड सैय्यद इश्फाक, एआईएसएफ के दिल्ली राज्य सह सचिव कॉमरेड संतोष कुमार, एसएफआई के दिल्ली राज्य सह सचिव कॉमरेड अमन और एआईडीएसओ के महासचिव कॉमरेड शिवाशीष प्रहराज ने सभा को संबोधित किया

सभी वक्ताओं ने बताया कि यह कदम एक बेहद अलोकतांत्रिक और फासीवादी हमला है और उन्होंने शिक्षा, लोकतंत्र व धर्मनिरपेक्षता पर एनईपी-'20 के हमले और अन्य हमलों के खिलाफ एक संयुक्त वामपंथी और लोकतांत्रिक आंदोलन खड़ा करने पर जोर दिया।

सत्र का संचालन जेएनयू की पीएचडी शोध छात्रा और एआईडीएसओ दिल्ली राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड सुमन ने किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता एआईडीएसओ के दिल्ली राज्य अध्यक्ष कॉमरेड डॉ. अनिरबन भौमिक ने की। अंत में, एआईडीएसओ, दिल्ली की उपाध्यक्ष कॉमरेड सौम्या सामल ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए वक्ताओं, प्रतिभागियों और वालन्टियरों को धन्यवाद दिया।

एआईयूटीयूसी का कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर

सोनीपत : शिक्षण शिविर में बात रखते हुए कॉमरेड के. राधाकृष्ण

सोनीपत (हरियाणा) : एआईयूटीयूसी हरियाणा प्रदेश कमेटी द्वारा दो दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर 1 से 2 नवंबर को स्थानीय आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आयोजित किया गया।

इस प्रशिक्षण शिविर का संचालन एआईयूटीयूसी के अखिल भारतीय अध्यक्ष कॉमरेड के.राधाकृष्ण व महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्त ने किया। इसमें एआईयूटीयूसी कार्यकर्ताओं की अच्छी भागीदारी रही।

सोनीपत : शिक्षण शिविर में बात रखते हुए कॉमरेड शंकर दासगुप्त

श्रम कानूनों में बदलाव .....

(पृष्ठ 1 का शेष)

लंबे समय से श्रम कानून सुधारों की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन इन सुधारों का यह मतलब नहीं है कि मालिकों ने पहले से ही श्रमिकों के रोजगार और कार्य स्थितियों में जो तमाम अनियमितताएं, अन्याय, अमानवीय और गैरकानूनी चीजें थोप रखी हैं, उन्हें दूर करने के लिए मौजूदा कानूनों में बदलाव किया जाएगा। बल्कि इसके विपरीत मजदूरों के जो भी कानूनी अधिकार अभी बचे हुए हैं, जो अधिकार मजदूरों ने लंबे संघर्ष से हासिल किये थे, जैसे स्थायी रोजगार, आठ घंटे काम, सेवानिवृत्ति पर भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेन्शन और कई तरह की सामाजिक सुरक्षाएं आदि दी जाती हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया जाए और मालिकों को यह छूट दे दी जाए कि मजदूरों को वे अपनी मनमर्जी से जब चाहे काम पर रखें और जब चाहें नौकरी से निकाल सकें। इसी को उन्होंने श्रम कानून सुधार का नाम दिया है। श्रम सुधारों के नाम पर केंद्र और राज्य सरकारें बस यही कर रही हैं।

1999 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र की भाजपा सरकार ने कांग्रेस सांसद विजय वर्मा के नेतृत्व में द्वितीय राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था। इस आयोग ने 2002 में देश के सभी श्रम कानूनों को एक संहिता में बदलने का प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव में मालिक वर्ग के हित में श्रमिकों के अधिकारों को छीनने की बात कही गयी थी। 2020 में मोदी सरकार ने कोरोना महामारी का लाभ उठाते हुए संसद में चर्चा का कोई अवसर दिये बिना अत्यंत अलोकतांत्रिक तरीके से लेबर कोड (श्रम संहिताएं) पारित कर दिये।

नई श्रम संहिताओं में 'नियत अवधि का रोजगार' यानी ठेका-आधारित काम लागू किया गया है। नतीजतन, इस संहिता के जरिए लंबे समय से चली आ रही स्थायी नौकरियों के लिए स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। नतीजतन, मालिकों द्वारा किये जा रहे शोषण-उत्पीड़न की मार भी बढ़ गयी है।

स्थायी नौकरियां खत्म करने के अलावा, अब सरकारों ने कानून बनाकर काम के घंटे भी बढ़ा दिये हैं। सरकार और मालिकों का तर्क है कि 12 घंटे का कार्य दिवस उत्पादन बढ़ायेगा। पूंजीपति निवेश में रुचि लेंगे। अगर काम के घंटे आठ घंटे की बजाय 12 घंटे कर दिये जाएं, तो उत्पादन बढ़ जायेगा।

पूंजीपति भी निवेश करने में रुचि ले सकते हैं। लेकिन मजदूर भी तो उत्पादन में समान रूप से हिस्सेदार हैं। क्योंकि बगैर श्रम के कुछ भी उत्पादन करना संभव नहीं है और यह श्रम मजदूरों से ही मिलता है। तब क्या एक जनवादी सरकार, जन कल्याणकारी कहलाने वाली सरकार सिर्फ मालिकों का ही हित क्यों देखेगी?

मजदूरों के हित का ध्यान रखना सरकार की ही जिम्मेदारी है। फिर सरकारें ऐसे एकतरफा कानून क्यों लाती हैं? कहते हैं कि कानून की नजर में सब बराबर हैं। लेकिन किसी पूंजीवादी व्यवस्था में कानून सबके लिए बराबर नहीं होता, यह मालिक और मजदूर, दोनों के लिए पूरी तरह से एक-दूसरे के विपरीत होता है, इस संशोधन ने यह स्पष्ट कर दिया है। जो कानून मालिकों को मजदूरों पर शोषण का बुलडोजर चलाने का अधिकार देता है और उन्हें मुनाफे के अंबार लगाने में मदद करता है, वही कानून मजदूरों को गुलामी की ओर, भुखमरी की ओर धकेल रहा है और उनका जीना मुश्किल कर रहा है। जो कानून मालिक को मजदूरों का मनमाना शोषण करने का अधिकार देता है, वह मजदूर को उसका विरोध करने का कोई अधिकार नहीं देता। इससे साबित होता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में कानून चाहे कितना भी कर्णप्रिय क्यों न लगता हो, अंततः वह मालिक वर्ग के हित साधता है। कानून में यह बदलाव साबित करता है कि पूंजीवादी व्यवस्था में देश का असली मालिक पूंजीपति वर्ग ही है। इस व्यवस्था में मजदूर के जीवन का कोई मूल्य नहीं है।

जब तक समाजवादी खेमा मौजूद था, तब तक पूंजीवादी देशों को भी कल्याणकारी राज्य होने का लबादा ओढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। मालिकों को कम से कम कुछ हद तक तो मजदूरों को उनका वाजिब हक देना ही पड़ा था। समाजवादी खेमे के न रहने पर जैसे-जैसे पूंजीवादी राज्यों ने अपना कल्याणकारी लबादा उतार फेंका है, वैस-वैसे ही मालिक भी बेपरवाह होते चले गए। उन्हें किसी कानून या नीति की कोई परवाह नहीं है।

प्रधानमंत्री और भाजपा नेता पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था या तीसरे-चौथे नंबर की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनने की बात करते हैं। देश के आम आदमी की क्रय शक्ति कम होने से घरेलू बाजार चरमरा रहा है। हजारों कारखाने बंद पड़े हैं। रोजाना और बंद हो रहे हैं। देश बेरोजगारों से भरा पड़ा है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। युवा शराब और नशे की लत में फंस रहे हैं। मंत्रीगण किस आधार पर इतनी प्रगति की बात कर रहे हैं? दरअसल, श्रम कानूनों में ये सुधार इसीलिए किये जा रहे हैं ताकि मजदूरों को उनके वाजिब अधिकारों से वंचित करके और उन पर और बोझ डालकर उत्पादन की लागत कम की जा सके और मालिकों का मुनाफा बढ़ाया जा सके। इस तरह मजदूरों पर शोषण बढ़ता ही जा रहा है।

वे इस तथाकथित प्रगति को मालिकों का मुनाफा बढ़ाकर ही हासिल करना चाहते हैं। शोषित-उत्पीड़ित जनता की मुक्ति के प्रणेता कार्ल मार्क्स ने बहुत पहले कहा था कि मालिक का मुनाफा मजदूर को उसके वाजिब हक, उसके श्रम के फल से वंचित करके होता है। श्रम समय बढ़ाने की यह घटना मार्क्स के शब्दों की सत्यता को एक बार फिर सही साबित करती है।

सरकार और मालिक जिस विकास की बात कर रहे हैं, वह विकास मजदूरों को पूरी तरह लूटकर किया जा रहा है। उस विकास में मजदूरों को अतिरिक्त श्रम और उत्पीड़न के बोझ के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। इसमें सिर्फ मालिकों का विकास है। फिर भी, मालिक, राजनेता और मंत्री यह दिखाना चाहते हैं कि यही देश का विकास है। जिस तरह से सरकारें, चाहे किसी भी पार्टी की हों, श्रम कानूनों में बदलाव ला रही हैं, किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि यह किसी पार्टी विशेष की नीति नहीं है, बल्कि देश के मालिक वर्ग की इच्छा है और मांग है, जिसे विभिन्न बुर्जुआ और पेटी-बुर्जुआ पार्टियों द्वारा चलायी जा रही सरकारें पूरी कर रही हैं और उनकी ताबेदारी कर रही हैं। कई लोग 'इंडिया' गठबंधन को भाजपा का विकल्प मानते हैं। वास्तव में, यह स्पष्ट है कि इस तथाकथित विपक्षी गठबंधन की पार्टियों द्वारा संचालित सरकारें भी मालिक वर्ग के हितों के लिए उसी तरह मजदूरों के हितों के विरुद्ध भूमिका निभा रही हैं, जैसे शासक पार्टी की सरकारें। इसलिए आज पार्टी का रंग नहीं, झंडा नहीं, बल्कि पार्टी का वर्ग चरित्र देखने की जरूरत है कि पार्टी किस वर्ग का हित साध रही है। आज तथाकथित विपक्षी पार्टियों की समझौता परस्त भूमिका के कारण ही भाजपा सरकार इतनी बेपरवाह होकर मजदूरों के हितों के विरुद्ध ये श्रम संहिताएं लाने में सफल हो पायी है। वह अब 12 घंटे काम करने का नियम लागू कर पा रही है।

ऐतिहासिक मई दिवस मजदूरों के शोषण के खिलाफ और आठ घंटे के कार्य दिवस की मांग के लिए संघर्ष का दिन है। वर्तमान में, पूंजीवादी शासन और पूंजीवादी वैश्वीकरण, मजदूर आंदोलन की कमजोरी का फायदा उठाकर मई दिवस की उपलब्धियों को मटियामेट करने पर उतारू है। ऐसे में, मजदूर वर्ग का यह कर्तव्य है कि वह केंद्र व राज्य सरकारों की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन खड़ा करे। मजदूर आंदोलन पहले से ही हर देश में बड़े पैमाने पर खड़ा हो रहा है। इस देश के मजदूर भी चुप नहीं बैठेंगे। सड़कों पर उनका विरोध भी जरूर फूट पड़ेगा।

मार्क्सवाद के तीन स्रोत तथा तीन संघटक अंग

— वी.आई. लेनिन

पूरे सभ्य जगत में मार्क्स की शिक्षाओं को पूंजीवादी विज्ञानों के समस्त क्षेत्रों में (सरकारी भी और उदारतावादी भी) अत्यंत द्वेष और घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, पूंजीवादी विज्ञान मार्क्सवाद को एक प्रकार का "खतरनाक पंथ" समझता है। इसके अतिरिक्त और किसी रवैये की आशा भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वर्ग संघर्ष पर आधारित समाज में "निष्पक्ष" सामाजिक विज्ञान हो ही नहीं सकता। समस्त सरकारी तथा उदारतावादी विज्ञान किसी न किसी ढंग से मजूरी पर आधारित (उजरती) दासता की रक्षा करता है, जबकि मार्क्सवाद मजूरी पर आधारित दासता के खिलाफ अंत तक लड़ने की घोषणा कर चुका है। ऐसे समाज में, जिसमें मनुष्य मजूरी के लिए दास बन जाता हो विज्ञान से निष्पक्ष होने की आशा करना उतनी ही बड़ी मूर्खता है, जितनी कि उद्योगपतियों से इस प्रश्न पर निष्पक्षता की आशा करना कि पूंजी के मुनाफे में कमी करके क्यों न मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी जाये।

परंतु बात इतनी ही नहीं है। दर्शनशास्त्र का इतिहास और सामाजिक विज्ञान का इतिहास पूर्ण स्पष्टता के साथ इस बात को बताता है कि मार्क्सवाद में "पंथवाद" जैसी कोई चीज नहीं है, इस अर्थ में कि वह कोई ऐसा रूढ़िबद्ध, जड़ मत हो, ऐसा मत, जो विश्व सभ्यता के विकास के प्रशस्त मार्ग से हटकर कहीं अलग से उत्पन्न हुआ हो। इसके विपरीत, मार्क्स की प्रतिभा इसी बात में निहित है कि उन्होंने ऐसे प्रश्नों के उत्तर मालूम किये, जिन्हें मानवजाति के प्रमुखतम विचारक पहले ही उठा चुके थे। उनकी शिक्षाएं दर्शनशास्त्र, राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा समाजवाद के श्रेष्ठ प्रतिनिधियों की शिक्षाओं के प्रत्यक्ष तथा सन्निकट क्रम के रूप में ही उत्पन्न हुईं।

मार्क्सीय विचारधारा इसलिए सर्वशक्तिमान है कि वह सत्य है। वह सम्पूर्ण तथा सुसंगत है और मनुष्य को विश्व के बारे में एक ऐसी अखंड अवधारणा प्रदान करती है, जिसका किसी भी प्रकार के अंधविश्वास, प्रतिक्रिया या पूंजीवादी उत्पीड़न की रक्षा से कोई भी समझौता असंभव है। उन्नीसवीं शताब्दी में जर्मन दर्शनशास्त्र, अंग्रेजों के राजनीतिक अर्थशास्त्र तथा फ्रांसीसी समाजवाद के रूप में मानव-जाति की जो भी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं थीं, मार्क्सवाद उनका ही वैध उत्तराधिकारी है।

हम मार्क्सवाद के इन्हीं तीन स्रोतों पर, जो साथ ही उसके संघटक अंग भी हैं, संक्षेप में विचार करेंगे।

1

मार्क्सवाद का दार्शनिक सिद्धांत भौतिकवाद है। यूरोप के पूरे आधुनिक इतिहास में, और विशेष रूप से अठारहवीं शताब्दी के अंत में फ्रांस में, जो हर प्रकार के मध्ययुगीन कचरे के खिलाफ, संस्थाओं तथा विचारों में दासता के खिलाफ एक निर्णायक युद्ध का रणस्थल बना हुआ था, भौतिकवाद एकमात्र ऐसा दर्शन सिद्ध हुआ है, जो सुसंगत है, प्राकृतिक विज्ञान की समस्त शिक्षाओं की कसौटी पर खरा उतरता है और अंधविश्वास, तंत्र-मंत्र आदि का विरोधी है। इसलिए जनवाद के शत्रुओं ने भौतिकवाद का "खंडन करने", उसकी जड़ खोखली करने और उसे कलंकित करने की पूरी चेष्टा की और दार्शनिक भाववाद के विविध रूपों का प्रचार किया, जिसका अर्थ हमेशा, किसी न किसी रूप में, धर्म का पक्ष लेना या उसका समर्थन होता है।

मार्क्स तथा एंगेल्स ने अत्यंत दृढ़ संकल्प के रूप में दार्शनिक भौतिकवाद की रक्षा की और बार-बार इस बात को समझाया कि इस आधार से किसी भी दिशा में हटना कितनी भारी भूल है। एंगेल्स की 'लुडविग फायरबाख' तथा 'ड्यूहरिंग मतखंडन' नामक रचनाओं में उनके विचारों की अत्यंत सुस्पष्ट तथा पूर्ण व्याख्या की गयी है, 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' की तरह ही ये रचनाएं भी हर वर्ग-चेतन मजदूर के लिए गुटिकाएं हैं।

परंतु मार्क्स अठारहवीं शताब्दी के भौतिकवाद पर आकर रुक नहीं गये, उन्होंने दर्शनशास्त्र को आगे बढ़ाया। उन्होंने उसे जर्मन क्लासिकीय दर्शनशास्त्र की उपलब्धियों से, विशेषत: हेगेल की उस दर्शन-पद्धति की उपलब्धियों से समृद्ध किया, फायरबाख का भौतिकवाद हेगेल की ही दर्शन-पद्धति का परिणाम था। इन उपलब्धियों में सबसे मुख्य उपलब्धि द्वंद्वात्मकता का सिद्धांत है, अर्थात अपने पूर्णतम तथा गूढ़तम रूप में विकास का सिद्धांत, जो एकांगीपन से सर्वथा मुक्त है, मानव ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, जिसमें हमें सतत विकासमान पदार्थ का प्रतिबिंब मिलता है। पूंजीवादी दार्शनिकों की शिक्षाओं के बावजूद, जो "नये सिरे से" फिर पुराने सड़े हुए भाववाद की शरण में जा रहे हैं, प्राकृतिक विज्ञान के नवीनतम अनुसंधानों ने—रेडियम, इलेक्ट्रोन, तत्वों के रूपांतरण ने —मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सराहनीय पुष्टि की है।

दार्शनिक भौतिकवाद को और गहरा बनाकर और उसे विकसित करके मार्क्स ने उसे पूर्णता प्रदान की, उसके प्रकृति के ज्ञान को मानव समाज के ज्ञान तक पहुंचाया। मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वैज्ञानिक विचारों की सबसे बड़ी सफलता थी। उससे पहले इतिहास तथा राजनीति से संबंधित दृष्टिकोणों के क्षेत्र में जो अराजकता और स्वेच्छाचारिता फैली हुई थी, उसके स्थान पर एक ऐसे अत्यंत एकाकार तथा सामंजस्यपूर्ण विज्ञान-निष्ठ सिद्धांत की स्थापना हुई, जो बताता है कि किस प्रकार उत्पादक शक्तियों के विकास के फलस्वरूप सामाजिक जीवन की एक व्यवस्था में से एक दूसरी और उच्चतर व्यवस्था का विकास होता है—उदाहरण के लिए, किस प्रकार सामंतवाद में से पूंजीवाद का विकास होता है।

जिस प्रकार मनुष्य का ज्ञान प्रकृति (अर्थात विकासमान पदार्थ) को प्रतिबिंबित करता है, जिसका अस्तित्व मनुष्य से स्वतंत्र है, उसी प्रकार उसका सामाजिक ज्ञान (अर्थात उसके विविध दृष्टिकोण तथा मत—दार्शनिक, धार्मिक, राजनीतिक आदि) समाज की आर्थिक व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है। राजनीतिक संस्थाएं आर्थिक नींव के ऊपर खड़ा एक ऊपरी ढांचा होती हैं। उदाहरण के लिए, हम देखते हैं कि आधुनिक यूरोपीय राज्यों के विभिन्न राजनीतिक रूप सर्वहारा वर्ग पर पूंजीपति वर्ग के शासन को सुदृढ़ बनाने के काम देते हैं।

मार्क्स का दर्शन परिमार्जित दार्शनिक भौतिकवाद है, जिसने मानवजाति को, विशेष रूप से मजदूर वर्ग को ज्ञान के शक्तिशाली साधन प्रदान किये हैं।

2

इस बात को जान लेने के बाद कि आर्थिक व्यवस्था ही वह नींव होती है, जिस पर राजनीतिक ढांचे का निर्माण किया जाता है, मार्क्स ने सबसे अधिक ध्यान इसी आर्थिक व्यवस्था के अध्ययन की ओर दिया। मार्क्स की प्रमुख रचना 'पूंजी' आधुनिक, अर्थात पूंजीवादी समाज की आर्थिक व्यवस्था के ही अध्ययन को अर्पित है।

"लोग अपने भोलेपन के कारण राजनीति में दूसरे के हाथों धोखा खाते आये हैं और अपने आपको धोखा देते आये हैं और जब तक वे हर नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वायदे के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक वे इसी तरह धोखे का शिकार होते रहेंगे।"

मार्क्स से पहले क्लासिकीय राजनीतिक अर्थशास्त्र की उत्पत्ति इंगलैंड में हुई थी, जो पूंजीवादी देशों में सबसे उन्नत देश था। ऐडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक व्यवस्था के विषय में अपनी गवेषणाओं द्वारा श्रम द्वारा मूल्य के निर्धारण के सिद्धांत की नींव डाली। मार्क्स ने उनके काम को और आगे बढ़ाया। उन्होंने इस सिद्धांत को पूरी तरह सिद्ध कर दिया और बड़े सुसंगत रूप से इस सिद्धांत को विकसित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हर माल का मूल्य इस बात से निर्धारित होता है कि उसके उत्पादन में सामाजिक दृष्टि से आवश्यक श्रम-काल कितना लगाया गया।

जबकि पूंजीवादी अर्थशास्त्र वेत्ताओं ने वस्तुओं के पारस्परिक संबंध (एक माल के बदले में दूसरे माल के विनिमय) को देखा था, मार्क्स ने मनुष्यों के पारस्परिक संबंध का रहस्योद्घाटन किया। मालों का विनिमय मंडी के माध्यम से अलग-अलग उत्पादकों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। मुद्रा इस बात की द्योतक है कि यह संबंध निरंतर घनिष्ठतर होता जा रहा है और अलग-अलग उत्पादकों के आर्थिक जीवन को एक समष्टि के रूप में अभिन्न रूप से बांधे दे रहा है। पूंजी इस संबंध के विकास की अगली मंजिल है: मनुष्य की श्रम-शक्ति एक बिकाऊ माल बन जाती है। मजूरी लेकर काम करने वाला मजदूर अपनी श्रम-शक्ति को भूमि, कारखाने तथा श्रम के साधनों के मालिकों के हाथ बेच देता है। मजदूर कार्य-दिवस का एक भाग स्वयं अपने और अपने परिवार के भरण-पोषण का खर्च जुटाने के लिए व्यय करता है (मजदूरी), और दिन के शेष भाग में वह बिना पारिश्रमिक के श्रम करता है और इस प्रकार पूंजीपति के लिए अतिरिक्त मूल्य का सृजन करता है, जो मुनाफे का स्रोत है, पूंजीपति वर्ग की संपदा का स्रोत है।

अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है।

मजदूर के श्रम द्वारा उत्पन्न की गयी पूंजी छोटे-छोटे मालिकों को तबाह करके बेरोजगारों की एक पलटन तैयार करके स्वयं मजदूर के लिए एक बोझ बन जाती है। उद्योग-धंधों में तो बड़े पैमाने के उत्पादन की विजय तुरंत स्पष्ट हो जाती है, परंतु कृषि में भी हम यही क्रिया देखते हैं: बड़े पैमाने की पूंजीवादी कृषि की श्रेष्ठता बढ़ती जाती है, मशीनों का उपयोग बढ़ता जाता है, किसानी अर्थव्यवस्था के गले में मुद्रा-पूंजी का फंदा पड़ जाता है, उसका ह्रास होने लगता है और अपनी पिछड़ी हुई प्रविधि के बोझ के नीचे दबकर वह तबाह हो जाता है। कृषि में छोटे पैमाने के उत्पादन का ह्रास भिन्न रूप धारण करता है, परंतु यह बात है कि ह्रास होता है एक अकाट्य सत्य है।

छोटे पैमाने के उत्पादन को तबाह करके पूंजी इसके बाद श्रम की उत्पादिता में वृद्धि करती है और बड़े पूंजीपतियों के संगठनों के लिए इजारेदारी की स्थिति उत्पन्न करती है। उत्पादन स्वयं अधिकाधिक सामाजिक रूप धारण करता जाता है—लाखों-करोड़ों मजदूर एक सुव्यवस्थित आर्थिक संगठन में एक-दूसरे से बंध जाते हैं—परंतु इस सामूहिक श्रम द्वारा उत्पादित वस्तुओं को मुट्ठीभर पूंजीपति हड़प लेते हैं। उत्पादन की अराजकता और इसके साथ ही, संकट, मंडियों की बेतहाशा तलाश और जनसाधारण की जीवन-वृत्ति में अनिश्चितता बढ़ती जाती है।

पूंजी पर मजदूरों के परावलम्बन को बढ़ाने के साथ ही पूंजीवादी व्यवस्था समूहबद्ध श्रम की महान शक्ति को जन्म देती है।

मार्क्स ने माल-उत्पादन पर आधारित अर्थव्यवस्था के प्रथम अंकुरों से लेकर, साधारण विनिमय से लेकर उसके उच्चतम रूप, अर्थात बड़े पैमाने के उत्पादन तक पूंजीवाद के विकासक्रम का पता लगाया।

और पुराने तथा नये, सभी पूंजीवादी देशों का अनुभव वर्ष प्रति वर्ष अधिकाधिक मजदूरों के सामने इस मार्क्सीय सिद्धांत के सत्य को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कर रहा है।

पूंजीवाद ने सारे संसार में विजय प्राप्त कर ली है, परंतु यह विजय पूंजी पर श्रम की विजय की भूमिका मात्र है।

3

जब सामंतवाद का तख्ता उलट दिया गया और ईश्वर की इस पृथ्वी पर "स्वतंत्र" पूंजीवादी समाज का उदय हुआ, तब यह बात तुरंत स्पष्ट हो गयी कि इस स्वतंत्रता का अर्थ श्रमिकों के शोषण-उत्पीड़न की एक नयी व्यवस्था था। इस उत्पीड़न के प्रतिबिंब के रूप में और इसके विरोध में फौरन विविध प्रकार के समाजवादी मत जन्म लेने लगे। परंतु प्रारंभिक समाजवाद काल्पनिक समाजवाद था। वह पूंजीवादी समाज की आलोचना करता था, उसकी निंदा करता था और उसे कोसता था, वह उसके विनाश के स्वप्न देखता था, वह एक बेहतर व्यवस्था की सुखद कल्पनाओं में मगन रहता था और इस

(शेष पृष्ठ 7 पर)

जालन्धर में गदरी बाबाओं के मेले में जन शिक्षा नीति के ड्राफ्ट का विमोचन

जालंधर (पंजाब) : गदरी बाबाओं की याद में लगने वाले 30 अक्तूबर से 1 नवम्बर तक तीन दिवसीय मेले में ऑल इंडिया सेव एजुकेशन कमेटी की तरफ से प्रकाशित 'जन शिक्षा नीति-2025 एनईपी-2020 का एक विकल्प (ड्राफ्ट) पुस्तक का विमोचन किया गया। कमेटी की ओर प्रिंसीपल शारदा दीक्षित ऊपर तस्वीर में बायीं तरफ

जालन्धर में गदरी बाबाओं के मेले में लगायी पार्टी साहित्य की बुक स्टॉल

'भाव दो, खाद दो' की मांग को लेकर जुटे किसान

भोपाल (मध्य प्रदेश) : संयुक्त किसान मोर्चा, मध्य प्रदेश द्वारा 'भाव दो-खाद दो आंदोलन' के तहत 27 अक्तूबर को यहां के शाहजहानी पार्क में सभा की गई, जिसमें एआईकेकेएमएस के साथी भी शामिल हुए।

एआईकेकेएमएस की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष कॉमरेड सोनू शर्मा ने सभा को संबोधित किया।

बिहार में हो रही मुजरिमाना वारदातों पर रोक लगाओ —एसयूसीआई (सी)

पटना, 1 नवम्बर:

विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार में हो रही राजनीतिक हत्याओं और बाहुबल व धनबल के प्रदर्शन पर चिंता प्रकट करते हुए एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के राज्य सचिव कॉमरेड अरुण कुमार सिंह ने कहा कि मोकामा में एक दल विशेष के चुनाव प्रचार पर हमला और एक व्यक्ति की दिनदहाड़े हत्या और सीवान में एक पुलिस अधिकारी की हत्या बिहार की बिगड़ती कानून-व्यवस्था और अपराध-पोषक राजनीति की भयावह सच्चाई को उजागर करती है। ये घटनाएं यह साबित करती हैं कि बिहार की राजनीति में अपराधी तत्वों का दबदबा बढ़ चुका है और उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

उन्होंने कहा कि सत्तालोलुप पार्टियां जिस तरह से राज्य में चुनाव प्रचार के दौरान बाहुबल और धनबल का प्रदर्शन कर रही हैं, उससे आम नागरिक बेहद चिंतित और खौफजदा हैं। ऐसे में प्रशासन और चुनाव आयोग का यह कर्तव्य बनता है कि वे हर मतदाता के निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की स्थिति तैयार करें ताकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव हो सके वरना चुनाव एक ढकोसला बनकर रह जायेगा।

कॉमरेड सिंह ने राज्य में हो रही मुजरिमाना वारदातों के दोषियों को अविलंब गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा देने और ऐसी वारदातों को रोकने में विफल व इनके लिए जिम्मेवार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की।

बाढ़, जलभराव और बरसाती पानी की निकासी की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

बवानी खेड़ा (भिवानी) : बाढ़ व जलभराव से बचाव, बरसाती पानी की निकासी और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास की मांग को लेकर 3 नवम्बर को यहां ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) का प्रतिनिधिमण्डल तहसीलदार, बवानी खेड़ा से मिला और बाढ़ग्रस्त इलाके के किसान-मजदूरों की समस्याएं उनके सामने रखी।

संगठन ने गत 13 अक्तूबर को भी उनके कार्यालय में ज्ञापन सौंपा था, लेकिन जब सरकार ने कोई राहत प्रदान नहीं की, तो आज फिर उन्हीं मांगों का ज्ञापन तहसीलदार, बवानी खेड़ा को दिया गया। ज्ञापन में हर किसान को जल भराव से जल्द से जल्द मुक्ति दिलाने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल में किसान संगठन के जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह सैनी, कॉमरेड फूलचंद सैनी, महेंद्र सिंह कटारिया, गुलाब नेहरा, ओमप्रकाश बोहल, जंगबीर, अशोक कुकड़ेजा और सुभाष कुकड़ेजा बलीयाली भी शामिल थे।

मिड-डे मील कर्मियों की सभा आयोजित

तावडू (हरियाणा) : अपनी मानदेय बढ़ोतरी, समय पर मानदेय के भुगतान, वर्दी भत्ता बढ़ाकर 2000 रुपये करने, ड्यूटी के अलावा और काम न लेने आदि मांगों को लेकर 25 अक्तूबर को हरियाणा के नूंह जिले के तावडू में एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध मिड-डे मील कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा की सभा आयोजित की गयी, जिसे एआईयूटीयूसी के राज्य अध्यक्ष कॉमरेड राजेंद्र सिंह ने संबोधित किया। एआईयूटीयूसी के राज्य सचिवमंडल के सदस्य कॉमरेड शेर सिंह मीरपुर और नूंह के जिला प्रभारी कॉमरेड बृजमोहन भी उपस्थित थे। तावडू, नूंह की सैकड़ों मिड-डे मील कर्मचारियों ने सभा में उत्साहपूर्वक भाग लिया।

मिड-डे मील रसोइयों के परिवारों के कुछ पुरुष सदस्य भी इसमें शामिल हुए।

पीने के पानी की किल्लत के खिलाफ

एआईकेकेएमएस ने सौंपा ज्ञापन

तोशाम (हरियाणा) : 30 अक्तूबर को तोशाम व आसपास के गांवो में पीने के पानी की भयंकर समस्या को लेकर जन संघर्ष समिति, तोशाम और ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन (एआईकेकेएमएस) ने जल घर, तोशाम में एक दिवसीय सांकेतिक धरना दिया।

धरने की अध्यक्षता निरंजन शर्मा ने की व जल संसाधन मंत्री, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ के नाम अधीक्षक अभियंता की मार्फत एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गयी कि पेयजल की सप्लाई हर रोज दी जानी चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए संगठन के जिला सचिव कॉमरेड बस्तीराम और जिला प्रधान कॉमरेड रोहतास सिंह ने बताया कि 2 महीने से तोशाम और आसपास के गांवो में 30 दिन में केवल तीन दिन पानी दिया जा रहा है, जबकि पीने के पानी की हर रोज जरूरत पड़ती है। उन्होंने बताया कि डिग्गी (जलघर) में नहरी पानी की सप्लाई बाधित होने पर ट्यूबवैल से पानी की पूर्ति की जाती है। वह अधिकारियों की लापरवाही के कारण नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आम जनता को काफी परेशानी उठानी पड़ती है व दूषित पानी पीने को

मजबूर होना पड़ रहा है। नतीजतन, काफी लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं।

धरने में महावीर शर्मा, पुरुषोत्तम गोड़, कर्मवीर, महेंद्र सिंह कटारिया और फूल चंद सैनी ने भी अपने विचार रखे। वक्ताओं ने बताया कि सरकार पीने का पानी भी पूंजीपतियों को सौंपना चाहती है ताकि प्राइवेट कंपनियां अकूत मुनाफा कमा सकें। सरकार लोगों को पर्याप्त मात्रा में बिजली-पानी, शिक्षा-रोजगार और रोटी-कपड़ा-मकान उपलब्ध कराने की अपनी जिम्मेवारी से पल्ला झाड़ रही है। वक्ताओं ने बताया कि हमारे पास अपनी सुविधाएं लेने के लिए आंदोलन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। उन सभी ने गांव-गांव में जन कमेटियां गठित करने और आंदोलन को तेज करने की अपील की।

प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने की नीति के खिलाफ बिजली उपभोक्ताओं का राज्य स्तरीय विरोध प्रदर्शन

हांसी : बिजली उपभोक्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए मेहर सिंह बांगड़

हांसी (हरियाणा) : केंद्र व राज्य सरकार की प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम व बिजली के निजीकरण के विरोध में ऑल इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर एसोसिएशन से सम्बद्ध बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा ने 28 अक्तूबर को यहां तहसील स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया।

सम्मेलन की अध्यक्षता रिटायर्ड एसडीओ कश्मीरी लाल ग्रोवर, बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के राज्य प्रधान इन्द्र सिंह मलिक व हांसी व्यापार मंडल के प्रधान प्रवीण तायल ने की।

एआईकेकेएमएस के राज्य सचिव व किसान मोर्चे के केंद्रीय कमेटी सदस्य जयकरण मांडोठी ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार बिजली जैसी बुनियादी जरूरत की सेवा को निजी कंपनियों के हाथों में देकर मुनाफाखोरी के माल में तब्दील करती जा रही है। इससे बिजली के रेट बढ़ते जा रहे हैं और बिजली आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। तीन काले कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चे द्वारा चलाये गये ऐतिहासिक किसान आंदोलन के दबाव में सरकार ने लिखित में यह आश्वासन दिया था कि संयुक्त किसान मोर्चा व अन्य स्टेक होल्डरों से विचार विमर्श के बगैर बिजली निजीकरण को लेकर बिजली बिल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। लेकिन अफसोस की बात है कि मोदी सरकार अपने वादे से मुकरते हुए बिजली वितरण प्रणाली को निजी कंपनियों के हवाले करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बिजली बिल 2023 संसद में पेश करने के बावजूद सरकार उसको कानून नहीं बनवा पायी। वह अभी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास लंबित है। लेकिन मोदी सरकार द्वारा उसको धता बताते हुए 9 अक्तूबर को नया बिल 2025 जारी किया गया है, जिसमें निजी कंपनियां व उद्योगपतियों के संगठनों से सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन बिजली उपभोक्ताओं, किसानों व बिजली कर्मचारियों, जो इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, को सुझाव देने के अधिकार से भी मोदी सरकार ने वंचित कर दिया है। इससे सरकार की मंशा को बखूबी समझा जा सकता है।

सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिजली उपभोक्ता मंच के राज्य सचिव मेंहर सिंह बांगड़ व राज्य प्रधान इंदर सिंह मलिक ने कहा कि भाजपा सरकार निजी कंपनियों के हित साधने के लिए ही स्मार्ट मीटर स्कीम लायी है। बिजली संशोधन बिल 2023 को सरकार अभी भी कानून नहीं बनवा पायी, लेकिन फिर भी रिवैंमपड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत उपभोक्ताओं के घरों पर जबरन स्मार्ट मीटर लगाये जा रहे हैं। इनका देशभर में जबरदस्त विरोध हो रहा है। जोरदार आंदोलन खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जहां भी ये मीटर लगे हैं, वहां उपभोक्ताओं का बिल हजारों रुपये, कहीं-कहीं तो लाखों रुपये तक बढ़ गया है। यह मीटर प्रीपेड डिवाइस के साथ (टीओडी) टाइम आफ डे यानी दिन के अलग-अलग समय अलग-अलग रेट चार्ज करने की क्षमता रखता है। जिस समय बिजली की ज्यादा खपत होती है, उस समय ज्यादा रेट चार्ज करने की क्षमता इस मीटर में है। आंदोलन के दबाव में कई सरकारों को इस योजना से कदम पीछे हटाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। हरियाणा में भी राज्य सरकार स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला ले चुकी है, जो कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए गले की फांस साबित होगा। इसलिए इसके खिलाफ जोरदार आंदोलन खड़ा करने की जरूरत है। वक्ताओं ने आम बिजली उपभोक्ताओं को इस जनविरोधी स्कीम के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए आगे आने की अपील की। सम्मेलन में कश्मीरी लाल ग्रोवर की अध्यक्षता में एक संघर्ष कमेटी का भी गठन किया गया, जो इस स्कीम के खिलाफ नवंबर महीने में हस्ताक्षर अभियान चलाकर लोगों को लगातार जागरूक करते हुए दिसंबर के पहले सप्ताह में एसडीएम, हांसी के माध्यम से मुख्यमंत्री व बिजली मंत्री, हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजेगी। संघर्ष कमेटी शहर व आसपास के गांवों में आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी।

रोघी खाप के प्रधान सुमेर सिंह जागलान ने खाप की तरफ से सम्मेलन को संबोधित करते हुए अपना पूरा समर्थन व्यक्त किया। सम्मेलन को किसान नेता धर्मपाल बडाला, हांसी शहीद यादगार समिति के अध्यक्ष कृष्ण एलावादी, एआईकेकेएमएस के भिवानी जिला प्रधान रोहताश सैनी, बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा के भिवानी जिला संयोजक महेंद्र सिंह कटारिया,केंद्रीय ट्रेड यूनियन एआईयूटीयूसी के जिला प्रधान सत्यनारायण भाटोल, इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा नैन, एटक के जिला प्रधान सुबे सिंह और भवन निर्माण कारीगर मजदूर यूनियन के जिला सचिव मास्टर विजेंद्र जीतपुरा ने भी संबोधित किया।

बहादुरगढ़ (हरियाणा) : प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम व बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ बिजली उपभोक्ता मंच हरियाणा ने राजकुमार सैनी की अध्यक्षता में यहां दो जगह लाइनपार रेलवे पार्क और चौ. छोटूराम धर्मशाला में बिजली उपभोक्ताओं की सभा आयोजित की।

बहादुरगढ़

भवन निर्माण श्रमिकों ने अपनी मांगों के लिए किया संयुक्त रोष प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन

हांसी (हरियाणा) : श्रमिक कल्याण बोर्ड की जून महीने से हरियाणा सरकार द्वारा बंद की गई वेबसाइट तुरंत चालू करने व अपनी अन्य मांगों को लेकर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एआईयूटीयूसी, इंटक और एटक से संबद्ध भवन निर्माण मजदूरों की यूनियनों की ओर से 28 अक्तूबर को शहर में जोरदार प्रदर्शन करते हुए एसडीएम, हांसी की अनुपस्थिति में रीडर संतोष कुमारी की मार्फत मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार को ज्ञापन भेजा गया।

इस अवसर पर एआईयूटीयूसी के हिसार जिला प्रधान कॉमरेड सत्यनारायण भाटोल, इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण नैन और एटक के जिला प्रधान सुबे सिंह ने बताया कि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व फर्जीवाड़ा उजागर होने पर भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के बहाने सरकार द्वारा विभाग की वेबसाइट को ही बंद कर दिया गया। इससे मजदूरों के सभी तरह के हितलाभ व पंजीकरण प्रक्रिया पर रोक लगने से वास्तविक मजदूरों को भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है।

मजदूर नेताओं ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से बंद की गयी वेबसाइट को तुरंत चालू करने, मजदूरों के रोके गए हितलाभ तुरंत जारी करने व पंजीकरण प्रक्रिया शुरू करने की मांग को जोरदार ढंग से उठाया गया।

उन्होंने बताया की वर्कस्लिप वेरिफिकेशन का कार्य यूनियनों द्वारा किया जाता था, लेकिन जब से वर्कस्लिप वेरीफिकेशन अधिकारियों को दिया गया है, तब से भवन निर्माण एवं सर्न्निमाण कल्याण बोर्ड में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ज्ञापन में मांग की गयी कि वर्कस्लिप वेरीफिकेशन यूनियनों द्वारा की जाए व हितलाभ की प्रक्रिया सरल की जाए और 15 दिन में पूरी की जाए। श्रमिक नेताओं ने कहा कि अगर मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया, तो पूरे हरियाणा में जोर-शोर से आन्दोलन किया जाएगा।

इस अवसर पर एआईयूटीयूसी के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड मेहर सिंह बांगड़ के अलावा कॉमरेड विजेंद्र जीतपुरा, सूरज भाटोल, सुखविंदर, शमशेर, जगमाल, संजय, पवन, शिव कुमार, कैलाश, वंदना ठाकुर, अंजू, शारदा, मुकेश, सुमित्रा, गुड्डी, शीला आदि भी मौजूद थे।

सक्रिय महिलाओं एनआरएलएम का एक दिवसीय धरना संपन्न

कोंडागांव : सक्रिय महिलाओं के धरने को सम्बोधित करते हुए कॉमरेड विश्वजीत हारोड़े

कोंडागांव (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जिला स्तरीय धरने देने के कार्यक्रम के अंतर्गत 30 अक्तूबर को जिला कोंडागांव, छत्तीसगढ़ में सक्रिय महिलाओं (CRP in NRLM) व पशु सखी व कृषि सखी का एक दिवसीय संयुक्त सभा व धरना संपन्न हुआ और कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, मुख्य सचिव, पंचायत सचिव और बिहान संचालक को ज्ञापन सौंपा गया।

सभा को सलाहकार कॉमरेड विश्वजीत हारोडे, प्रांतीय अध्यक्ष कॉमरेड पदमा पाटिल, जिलाध्यक्ष मधुबाला, जिला सचिव हेमन्तिन नाग व कोषाध्यक्ष आशा जैन आदि कई महिलाओं ने संबोधित किया।

एआईकेकेएमएस ने की 24 घंटे बिजली देने की मांग

बवानी खेड़ा (भिवानी) : 28 अक्तूबर को एआईकेकेएमएस, बवानी खेड़ा ब्लॉक कमेटी के एक शिष्टमंडल ने बिजली कार्यालय में अभियंता अधीक्षक से मुलाकात कर अधिक वर्षा से खेतों में जलभराव और बरसाती पानी की निकासी के लिए लगायी गयी बिजली की मोटरों को 24 घंटे बिजली सप्लाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन दिया।

जनसुविधाएं देने की उठी मांग

हिसार (हरियाणा) : 24 अक्तूबर को यहां लोगों की बुनियादी सुविधाओं-सड़क, बिजली, पानी, सीवर, खाली प्लाटों की सफाई आदि को लेकर सेक्टर-4 में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। उसके बाद प्रतिनिधिमंडल एचएसवीपी अधिकारियों व उपायुक्त हिसार से मिला व अन्य मांगों सहित सड़क निर्माण में ठेकेदार द्वारा की जा रही अनियमितताओं बारे में ज्ञापन सौंपा।

PRGI Regn. No. 43022

एक निर्माण मजदूर की नजरों में...

(पृष्ठ 1 का शेष)

के लिए कुछ नहीं है। वे सब पश्चिम में भाग गए हैं, अब वे शिकागो की प्रयोगशाला के अड्डों में बैठे हैं और वहां बैठे समाजवाद की बुराई कर रहे हैं। जबकि हम यहां बैठे हैं... रूस में। ... अब उन्होंने इससे अपने हाथ-पैर धो लिये हैं। आज जो चाहे, वो रूस के मुंह पर तमाचा मार सकता है। उन्होंने इसे घिसे-पिटे विदेशी कपड़ों और एक्सपायर हो चुकी दवाओं से भरे कबाड़खाने में बदल दिया है। कूड़ा-कचरा! ... कच्चे माल से भरा एक नाला, एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ... क्या यही थी सोवियत शासन व्यवस्था? यह पूरी तरह त्रुटिहीन कोई आदर्श व्यवस्था तो नहीं थी, लेकिन आज जो चल रही है, उससे तो वह सौ गुना बेहतर थी, कहीं ज्यादा उन्नत थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि समाजवाद से हम संतुष्ट थे: कोई भी बहुत ज्यादा अमीर या गरीब नहीं था। कहीं कोई बेघर नहीं था या कोई लावारिस बच्चा नहीं था। ... बूढ़े-बुजुर्ग लोग अपनी पेन्शन पर गुजारा कर सकते थे। उन्हें जिंदा रहने के लिए सड़क से बोतलें और जूठन के रूप में फेंके खाने के टुकड़े कूड़ेदान से चुगने नहीं पड़ते थे। वे आपको भीख मिलने की आशा में आंसुओं भरी निगाहों से ताकते हुए नहीं मिलते थे, वहां भिखारी हाथ पसारे खड़े नहीं मिलते थे। ... हमें अभी तक सही-सही यह हिसाब नहीं मालूम है कि पेरेस्त्रोइका के कारण कितने लोगों की मौत हो चुकी है।

हमारा पिछला जीवन एकदम तहस-नहस हो गया है, कुछ भी बाकी नहीं बचा है। बहुत जल्द, शायद वह दिन देखना पड़े, जब मेरे पास अपने बेटे से बात करने के लिए कुछ नहीं होगा। मेरा बेटा स्कूल से घर आते ही मुझसे कहे, "पापा, पावलिक मोरोजोव एक मंदबुद्धि है। मराट काजेई (युवा पायनियर, जो तेरह वर्ष की आयु में पार्टीजन सेना में शामिल हो गया और जर्मनों के साथ लड़ाई में एक हथगोले से खुद को मारने के लिए जिसे मरणोपरांत सोवियत संघ के हीरो की उपाधि दी गई थी।) एक सनकी था।" "लेकिन आपने तो मुझे सिखाया था...।" मैंने उसे वही सीख दी थी, जो सीख मुझे दी गयी थी। सही सीख–"उस भयानक सोवियत जीवनशैली..." उस "भयानक सोवियत जीवनशैली" ने मुझे सिर्फ खुद के बारे में न सोचकर दूसरों के बारे में सोचना सिखाया था। कमजोरों और पीड़ितों के बारे में सोचना सिखाया था। अबकी तरह महंगी पोशाक पहनने, केवल रंग-रूप को लेकर इतराने और रुपयों की पर्स लेकर ही मगन रहने वाले फिल्मी सितारे मेरे हीरो नहीं थे। बल्कि निकोलाई गैस्तैलो (सोवियत लाल फौज का एक वायु सेना का जवान, एक पायलेट, जो दूसरे विश्वयुद्ध में एक महत्वपूर्ण हवाई हमले में नाजियों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया था) जैसे वीर मेरे हीरो थे, न कि वह मैजेंटा स्पोर्ट्स कोट, जिसका फलसफा सिर्फ अपने बारे में सोचना है। "प्लीज, पापा, वो रूहानी बातें, वो मानवतावाद की बड़ी-बड़ी बातें मत शुरू करो।" उसने ये सब कहां से सीखा? वह सिर्फ बारह साल का है, लेकिन जानता तो है। आजकल लोग बदल गये हैं पूंजीवादी प्रभाव से। ... समझना होगा, यही वह दुनिया से सीखता है। मैं अब उसके लिए कोई मिसाल नहीं रहा।

मैंने येल्तसिन का समर्थन क्यों किया? उन्होंने सिर्फ यह कहकर लाखों लोगों का समर्थन बटोर लिया था कि पार्टी कार्यकर्ताओं के विशेषाधिकार रद्द कर दिये जाने चाहिए। मैं मशीन गन उठाकर कम्युनिस्टों पर गोली चलाने को हरदम तैयार था। मुझे यकीन था... दरअसल हमें समझ नहीं आ रहा था कि वे इसकी जगह हमारे लिए क्या तैयार कर रहे हैं। हमें इस बात की जरा भी भनक नहीं लग पायी कि अन्दरखाने येल्तसिन हमें किस ओर धकेल रहा था। एक बहुत बड़ा झूठ! येल्तसिन ने लाल झंडेवालों के खिलाफ आवाज उठायी और श्वेत गार्डों से हाथ मिला लिया। यह एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गयी थी। ... सवाल सठता है कि हम क्या चाहते थे? सुन्दर, सभ्य, मानवीय समाजवाद। ... और हमें मिला क्या? यह खून का प्यासा पूंजीवाद अब सड़कों पर दनदनाता फिर रहा है-- गोलीबारी, बमबारी जारी है। लोग यह पता लगा रहे हैं कि कियोस्क (कारखाने) कौन चलाते हैं और फैक्टरियों के मालिक कौन हैं। गैंगस्टर ऊपर पहुंच गए हैं... कालाबाजारी करने वाले और पैसा बदलने वालों ने सत्ता हथिया ली है।... चारों तरफ दुश्मनों, शिकारियों और गीदड़ों की टोली है!

मैं कभी भूल नहीं सकता। ... मैं भूल नहीं सकता कि हम व्हाइट हाउस के सामने कैसे खड़े थे। ... हम किसी और के फायदे के लिए वहां खड़े थे (आग से किसके शाहबलूत निकाल रहे थे)? ....

मेरे पिता एक सच्चे कम्युनिस्ट थे। एक नेक इन्सान थे। वे एक बड़ी फैक्ट्री में पार्टी के संगठनकर्ता थे। दूसरे विश्वयुद्ध में लड़े। मैंने उनसे कहा था, "यही आजादी आई है! हम एक स्वाभाविक सभ्य देश बनने जा रहे हैं।" ... उन्होंने जवाब दिया था, "तुम्हारे बच्चे नौकर बनें। क्या तुम सच में यही चाहते हो?" मैं जवान था, मेरी उम्र और बुद्धि अल्प थी, मैं नासमझ था ... मैं उन पर हंसा। हम बहुत ही भोले थे। सचमुच मुझे नहीं पता कि हालात ऐसे क्यों हो गए। हम ऐसा नहीं चाहते थे। हमारे मन में कुछ बिल्कुल अलग था। पेरेस्त्रोइका... इसके बारे में हम सभी की धारणा बिल्कुल अलग तरह की थी। हमने सोचा था कि यह लगता है कुछ अभिनव चीज है। [वह रुकता है।]

एक साल बाद, उन्होंने हमारा डिजाइन ब्यूरो बंद कर दिया और मैं और मेरी पत्नी बेरोजगार होकर सड़क पर आ गए। हम कैसे गुजारा किया करते थे? सबसे पहले, हम अपना सारा कीमती सामान हमारी सब किताबें, सोवियत सोना, हमारी जो भी कीमती चीजें थीं, उनको बाजार ले गए और बेच दीं। हफ्तों तक, हम सिर्फ उबले हुए आलू खाते रहे। फिर मैं "व्यापार" करने लग गया। मैंने अधजली सिगरेट के टोटे बेचने शुरू कर दिये। एक लीटर के जार में या तीन लीटर के जार में भरे सिगरेट के टोटे। ... मेरी पत्नी के माता-पिता (पेशे से कॉलेज के प्रोफेसर) उन्हें सड़क से इकट्ठा करते थे और मैं उन्हें बेचता था और लोग उन्हें खरीदते थे और उन्हें पीते थे। मैं खुद भी पीता था। मेरी पत्नी दफ्तरों में सफाई का काम करती थी। एक समय उसने कुछ ताजिकस्तानियों के लिए पेल्मेनी (पकोड़े) बेचे। हमें अपनी नासमझी की भारी कीमत चुकानी पड़ी। हम सब को। ... अब, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर मुर्गियां पालते हैं और वह दुख का रोना-धोना बंद नहीं करती। काश! हम समय को पीछे ले जा पाते और अतीत में लौट सकते। ... और मुझे यह कहने से कोई मत रोके-टोके कि ... ये सस्ते मसालेदार कुलछे-लच्छों-सी गुजरे जमाने की कुछ भूली-बिसरी यादें नहीं हैं।... (दिसंबर 1991 में रेड स्क्वायर पर हुए साक्षात्कारों से Secondhand Time by Svetlana Alexievich - 2016 p. 139-140)

कॉमरेड रामयश मिश्रा का देहांत

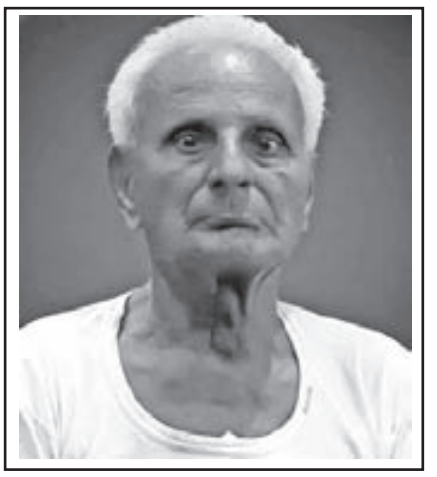

एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) के बिहार के मुजफ्फरपुर जिला कमेटी के पूर्व सदस्य तथा सकरा-मुरौल लोकल कमेटी के इंचार्ज, 92 वर्षीय कॉमरेड रामयश मिश्रा का निधन 16 अक्टूबर को हो गया। वे मुरौल प्रखंड के विशुनपुर श्रीराम पंचायत अन्तर्गत संभा गांव के निवासी थे।

कॉमरेड रामयश मिश्रा अपने रेलवे सेवा काल के दौरान ही इस देश के महान मार्क्सवादी चिन्तक कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों से गहराई से प्रभावित हुए। उसी काल में वे ट्रेड यूनियन आंदोलन से जुड़ गए और तत्पश्चात आजीवन पार्टी की विभिन्न जिम्मेदारियों को निष्ठापूर्वक निभाते रहे। 85 वर्ष की आयु के बाद भी वे सकरा-मुरौल क्षेत्र में साइकिल से नियमित रूप से पार्टी का साहित्य और अखबार आम जनता तक पहुंचाते रहे। संगठन की जिम्मेदारियों को निभाने में उनका समर्पण, अनुशासन और क्रांतिकारी निष्ठा सभी कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी।

कॉमरेड शिवदास घोष के विचारों और मार्क्सवादी चिंतन में उनका अटूट विश्वास ही उन्हें वृद्धावस्था तक सक्रिय और प्रेरित रखता रहा। कॉमरेड रामयश मिश्रा जी का जीवन और संघर्ष हम सबके लिए प्रेरणादायी रहेगा।

17 अक्तूबर को पार्टी के दिवंगत कॉमरेड रामयश मिश्रा को क्रांतिकारी सम्मान के साथ साथियों ने श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर सैंकड़ों ग्रामीण सहित भारी संख्या में पार्टी समर्थक भी उपस्थित रहे। पार्टी के बिहार राज्य सचिव एवं केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉमरेड अरुण कुमार सिंह की ओर से कॉमरेड कालिकांत झा ने रामयश मिश्रा के पार्थिव शरीर पर माल्यार्पण किया। पार्टी के मुजफ्फरपुर के जिला सचिव कॉमरेड अर्जुन कुमार की ओर से कॉमरेड काशी नाथ सहनी ने माल्यार्पण किया। मनियारी लोकल कमेटी, मुरौल लोकल कमेटी और मुशहरी लोकल कमेटी की ओर से कॉमरेड संजीत मांझी, कॉमरेड समोद ठाकुर और विपिन शाही ने माल्यार्पण किया। एआईयूटीयूसी की ओर से कॉमरेड राम सेवक पासवान, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की ओर से कॉमरेड वैद्यनाथ पंडित, कॉमरेड शत्रुध्न महतो और कॉमरेड विजय राम, ग्रामीण बुद्धिजीवी एवं सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद कुमार मिश्रा, उनके पुत्र शिव शंकर मिश्रा सहित दर्जनों समर्थकों ने माल्यार्पण किया। सभी ने 'मार्क्सवाद-लेनिनवाद-कॉमरेड शिवदास घोष चिंतनधारा जिंदाबाद!' व 'कॉमरेड रामयश मिश्रा को लाल सलाम!' के नारों के साथ नम आंखों से अपने प्रिय अभिभावक तुल्य कॉमरेड को अलविदा कहा।

कॉमरेड रामयश मिश्रा लाल सलाम।

महान क्रांतिकारी अशफाक उल्ला खां की जयंती मनायी

जौनपुर (उत्तर प्रदेश) : आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी धारा के महान क्रांतिकारी व काकोरी एक्शन के अमर शहीद अशफाक उल्ला खां की 125वीं जयंती यहां 22 अक्तूबर को श्री रामचंद्र जूनियर हाई स्कूल खजुरन बदलापुर, जौनपुर के प्रांगण में मनायी गयी। इसका आयोजन काकोरी-एक्शन शताब्दी वर्ष आयोजन समिति, जौनपुर द्वारा किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे।

कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यापक संजय यादव ने की और संचालन राकेश निषाद व पूनम प्रजापति ने संयुक्त रूप से किया। सभा को लालता प्रसाद यादव, अध्यापक राजेश सिंह, इंदु कुमार शुक्ल एडवोकेट, आयोजन समिति के कार्यालय सचिव संतोष कुमार प्रजापति, अपूर्व दूबे, नदीम असगर, अंजली सरोज और विवेक कुमार ने सम्बोधित किया।

कार्यक्रम में रूपा विश्वकर्मा, आजाद गुप्ता, विजय प्रकाश गुप्ता, दिलीप कुमार खरवार व अन्य ने क्रांतिकारी गीत प्रस्तुत किये। 'इंकलाब जिंदाबाद!' और 'अशफाक उल्ला खां अमर रहें!' के नारों के साथ समारोह का समापन हुआ।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन

तोशाम (हरियाणा) : तोशाम उपमण्डल स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने की मांग करते हुए जन संघर्ष कमेटी तोशाम के प्रतिनिधिमंडल ने 27 अक्तूबर को एसएमओ की मार्फत स्वास्थ्य मंत्री, हरियाणा सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा।

विश्व की 'पांचवीं' अर्थव्यवस्था वाले देश में हर घंटे एक से अधिक किसान कर रहे हैं आत्महत्या

'दीये तले अंधेरा'–यह उपमा विषमताओं से भरे भारत के संदर्भ में सौ प्रतिशत सच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर को एक सभा में दावा किया कि भारत अर्थव्यवस्था में विश्व में पांचवां स्थान हासिल करने जा रहा है। जबकि हाल ही में प्रकाशित एनसीआरबी की वर्ष 2023 की रिपोर्ट देश के आम लोगों की दुर्दशा की एक करुण तस्वीर प्रस्तुत करती है–जिसमें कहा गया है कि किसान और खेतिहर मजदूर मिलाकर 10,786 लोगों ने आत्महत्या की है।

इस दौर के सभी नेता-मंत्री अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह कोशिश करते रहे हैं कि किसान पारिवारिक कलह के कारण आत्महत्या करते हैं। लेकिन किसान परिवारों में इतना कलह हो क्यों रहा है–इसका जवाब तो सरकार को देना ही होगा। दरअसल, अन्य क्षेत्रों की तरह पूंजीवादी बाजार संकट के शिकार होकर कृषि पर निर्भर लोग भी अपना सब कुछ गंवा रहे हैं, जिसके नतीजतन उनका एक बड़ा हिस्सा मजबूर होकर आत्महत्या जैसा चरम कदम उठाने को विवश हो रहा है।

हाल ही में, जीएसटी घटाने की बात कहकर भाजपा सरकार ने यह दावा किया है कि अन्य नित्य-आवश्यक वस्तुओं की तरह कृषि उपकरणों के दाम भी बहुत कम हो गए हैं। वास्तविकता क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कब्जे में मौजूद कृषि में काम आने वाली चीजें, जैसे खाद-बीज-कीटनाशकों की असामान्य मूल्य वृद्धि के बाद इनके दाम मामूली-से कम होने से किसानों की समस्याओं का समाधान होना तो दूर रहा, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसके साथ जुड़ गए हैं सिंचाई के लिए बिजली और डीजल के बढ़ते दाम, वर्तमान में अनिवार्य हो चुका विभिन्न मशीनों का बढ़ा हुआ किराया, जिसने फसलों के उत्पादन की लागत को बहुत बढ़ा दिया है। इसके अलावा, फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तक न मिलना भी एक समस्या है। इस सबसे ऊपर, सरकार का कृषि और किसान-विरोधी दृष्टिकोण–ये सब मिलकर छोटे और मझोले किसानों को आज घोर मुसीबत में डाल रहे हैं। खेतिहर मजदूर, जो दूसरों की जमीन पर दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, किसानों की आय कम होने पर उनका काम भी छिन जाता है।

सितंबर में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि किसानों को कृषि उत्पादों का सही दाम नहीं मिल रहा है और इसके लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा है कि 2026-27 की रबी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ाने का निर्णय मंत्रिमंडल में लिया गया है। किसानों के लिए मंत्रियों की इतनी संवेदना के बावजूद, किसानों के जीवन में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? इससे पहले, 'आजादी का अमृतकाल महोत्सव' में 2025-26 की खरीफ फसल के लिए भी एमएसपी बढ़ाने की घोषणा हुई थी, जिसका खूब ढोल-नगाड़े पीट कर प्रचार भी किया गया था। केंद्र सरकार ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने की घोषणा की थी। चावल और गेहूं के मूल्य में मामूली बढ़ोतरी हुई थी। रागी, ज्वार, बाजरा, तिल, सोयाबीन, मक्का आदि में थोड़ी अधिक बढ़ोतरी हुई थी। जबकि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश थी कि सी$_2$+50% फार्मूले के अनुसार फसल की उत्पादन लागत का डेढ़ गुना एमएसपी दिया जाना चाहिए। उस हिसाब से धान का एमएसपी प्रति क्विंटल कम से कम तीन हजार रुपये होना चाहिए, जबकि सरकार ने केवल 2369 रुपये निर्धारित किया है। एकाधिकारी पूंजीपतियों के हित में भारत में अधिकांश लोगों के प्रमुख खाद्यान्न धान-गेहूं के बजाय सरकार निर्यात-बाजार की मांग के अनुसार अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है। उस क्षेत्र का मौसम, मिट्टी, सिंचाई व्यवस्था कैसी है–इसका विचार किये बिना, कई बार अवैज्ञानिक तरीके से खेती की व्यवस्था की जा रही है। नतीजतन, कई बार फसलों की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती और किसानों को उचित दाम भी नहीं मिल पाता है।

2021 के बाद से 2024-25 में सर्वाधिक 333 लाख टन गेहूं का उत्पादन हुआ है। लेकिन इस 'बम्पर' फसल में भी किसानों को सरकार द्वारा घोषित एमएसपी नहीं मिल रहा है। इस प्रकार, कई बार उत्पादन अधिक होने पर भी, उत्पादन लागत से एमएसपी कम होने के कारण किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारी पहल पर कृषि उत्पाद सीधे किसान से खरीदने की व्यवस्था न होने के कारण बिचौलिये और व्यापारी तरह-तरह के बहाने बनाकर किसानों को उत्पादन लागत से कम पैसे देते हैं। उत्पादित फसल को भंडारित करने का बुनियादी ढांचा सरकार अदानी से लेकर बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों के हाथों में सौंप रही है। वैसे भी आलू व अन्य साग-सब्जियों के संरक्षण की व्यवस्था सरकारी स्तर पर अत्यंत कम है। नतीजतन, किसान बार-बार नुकसान उठाते हैं। धान-गेहूं सहित कई अन्य फसलों के मामले में भी यही स्थिति है। सरकार किसानों के हित को न देखकर कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। किसान महाजनों से ऊंची दर पर कर्ज लेने के लिए मजबूर होते हैं। फसल की उत्पादन लागत से एमएसपी कम होने पर या प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने पर वे उस कर्ज को चुका नहीं पाते। उस समय किसानों का कर्ज माफ करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं दिखाई देती।

तो, क्या किसानों के हित में सरकार का सिर्फ प्रचार ही हो रहा है या वह वास्तव में गरीब, निर्धन किसानों के बारे में सोचती भी है? अगर सरकार सच में किसान का हित देखती, तो वह फसलों का उचित दाम मिलने की व्यवस्था करती, एमएसपी को कानूनन लागू करती और उत्पादन की लागत का डेढ़ गुना के हिसाब से फसलों के दाम निर्धारित करती।

भाजपा नेता कृषि के उत्पादन, भंडारण और बिक्री–सब कुछ को एकाधिकारी धनकुबेरों के हाथों में सौंपना चाहते हैं। वे देश के कृषि क्षेत्र को एकाधिकारी पूंजीपतियों के लिए खोल देने के उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। इस प्रकार, सरकार अदानी और अन्य एकाधिकारी पूंजीपतियों के हाथों में पूरे कृषि क्षेत्र और खाद्यान्न के व्यापार को सौंपना चाहती है।

क्योंकि सत्ताधारी पार्टियां और संसदीय विपक्षी पार्टियां सभी पूंजीपति वर्ग के राजनीतिक प्रबंधक के रूप में काम कर रही हैं। इससे बचने के लिए कृषि पर निर्भर लोगों को एकजुट होकर फसलों के उचित मूल्य की मांग के लिए और कृषि पर कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हमलों के विरोध में ऐतिहासिक किसान आंदोलन की तरह निरंतर आंदोलन खड़ा करना होगा। दिल्ली के बॉडरों पर हुए ऐतिहासिक किसान आंदोलन ने जिस तरह सरकार की किसान-विरोधी नीतियों का डटकर विरोध किया था और तीन काले कृषि कानूनों को वापस करवाया था, उसी तरह कृषि क्षेत्र को एकाधिकारी पूंजी के हाथों में पूरी तरह बेच दिये जाने के विरोध में आंदोलन को ही हथियार बनाना होगा। इस लड़ाई के रास्ते पर किसानों के सामने यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसानों की इस समस्या का मौलिक समाधान नहीं है। पूंजीपतियों के द्वारा किये जा रहे इस शोषण और लूट से बचने के लिए इस अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव लाना होगा।

दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़ती गुंडागर्दी का एआईडीएसओ ने किया विरोध

नई दिल्ली : बीआरएसी में हुई घटना के विरोध में अन्य छात्र संगठनों के साथ मिलकर एआईडीएसओ ने 17 अक्तूबर को डूसू कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया, जहां एबीवीपी सदस्य और डूसू की संयुक्त सचिव दीपिका झा ने एक प्रोफेसर को थप्पड़ मारा था। छात्रों द्वारा विरोधस्वरूप वहां एबीवीपी का पुतला भी फूंका गया। डीयू के सुरक्षा गार्डों ने कई प्रदर्शनकारियों के साथ बेरहमी से मारपीट की।

सभा को संबोधित करते हुए एआईडीएसओ की डीयू इकाई प्रभारी कॉमरेड अद्रिका ने कहा कि हम प्रो. सुजीत कुमार के साथ हैं। उन्होंने सभी छात्रों, शिक्षकों और शैक्षणिक जगत के सदस्यों सहित सभी वामपंथी एवं लोकतांत्रिक ताकतों से इस तरह की गुंडागर्दी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की।

मार्क्सवाद के तीन स्रोत ...

(पृष्ठ 3 का शेष)

बात का प्रयास करता था कि धनवान लोग शोषण की अनैतिकता पर विश्वास करने लगें।

परंतु काल्पनिक समाजवाद बाहर निकलने का सही रास्ता नहीं बता सका। वह न तो पूंजीवाद के अंतर्गत मजूरी पर आधारित दासता के सारतत्व की ही व्याख्या कर सका, न पूंजीवाद के विकास के नियमों का ही पता लगा सका और न उस सामाजिक शक्ति की ओर संकेत ही कर सका, जो एक नये समाज की रचयित्री बनने की क्षमता रखती है।

इसी दौरान सामंतवाद और कृषि दासता के पराभव के साथ यूरोपभर में, और विशेष रूप से फ्रांस में जो तूफानी क्रांतियां हुईं, उनसे यह बात अधिकाधिक स्पष्ट होती गयी कि इस पूरे विकास का आधार और उसकी प्रेरक शक्ति वर्गों का संघर्ष है।

सामंती वर्ग के खिलाफ राजनीतिक स्वतंत्रता की एक भी विजय ऐसी नहीं थी, जो घोर प्रतिरोध का सामना किये बिना प्राप्त की गयी हो। एक भी पूंजीवादी देश ऐसा नहीं है, जो पूंजीवादी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई के बिना न्यूनाधिक रूप में स्वतंत्र तथा जनवादी आधार पर विकसित हुआ हो।

मार्क्स की प्रतिभा इस बात में निहित है कि वे पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने इससे वह निष्कर्ष निकाला, जो विश्व इतिहास हमें सिखाता है और सुसंगत रूप से इस निष्कर्ष को लागू किया। यह निष्कर्ष वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है।

लोग अपने भोलेपन के कारण राजनीति में दूसरे के हाथों धोखा खाते आये हैं और अपने आपको धोखा देते आये हैं और जब तक वे हर नैतिक, धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक कथन, घोषणा और वायदे के पीछे किसी न किसी वर्ग के हितों का पता लगाना नहीं सीखेंगे, तब तक वे इसी तरह धोखे का शिकार होते रहेंगे। सुधारों और छोटे-मोटे हेर-फेर के समर्थक जब तक यह नहीं समझ लेंगे कि हर पुरानी संस्था, वह कितनी ही बर्बरतापूर्ण और सड़ी हुई क्यों न प्रतीत होती हो, कुछ शासक वर्गों के बल-बूते पर ही कायम रहती है, तब तक पुरानी व्यवस्था के संरक्षक उन्हें बेवकूफ बनाते रहेंगे। और इन वर्गों के प्रतिरोध को चकनाचूर करने का केवल एक ही तरीका है और वह यह कि जिस समाज में हम रह रहे हैं, उसी में उन शक्तियों का पता लगाना और उन्हें संघर्ष के लिए जागृत तथा संगठित करना, जो पुरातन को ढाहकर नूतन का सृजन कर सकने वाली शक्ति बन सकती हों–और अपनी सामाजिक स्थिति के कारण जिन्हें ऐसी शक्ति बनना चाहिए।

केवल मार्क्स के दार्शनिक भौतिकवाद ने ही सर्वहारा वर्ग को उस आत्मिक दासता से मुक्ति पाने का मार्ग दिखाया है, जिसमें सभी उत्पीड़ित वर्ग अब तक जकड़े दम तोड़ रहे थे। केवल मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत ने ही पूंजीवाद की सामान्य व्यवस्था में सर्वहारा वर्ग की वास्तविक स्थिति की व्याख्या की है।

अमरीका से लेकर जापान तक और स्वीडन से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक सारे संसार में सर्वहारा वर्ग के स्वतंत्र संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपना वर्ग संघर्ष चलाकर सर्वहारा वर्ग जागृत और शिक्षित हो रहा है, वह बुर्जुआ समाज के पूर्वाग्रहों के बंधन से मुक्त होता जा रहा है, वह अपनी पांतों को और भी घनिष्ठ रूप से लामबंद कर रहा है और अपनी सफलताओं को आंकना सीखता जा रहा है; वह अपनी शक्तियों को फौलादी बना रहा है और अदम्य वेग से आगे बढ़ रहा है। ●

3 मार्च, 1913 को प्रकाशित।
व्ला. इ. लेनिन, संग्रहित रचनाएं,
चौथा रूसी संस्करण, खंड 19, पृष्ठ 3-8

PRGI Regn. No. 43022

प्रधानमंत्री मोदी ने की ट्रंप और नेतन्याहू की सराहना

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 9 अक्टूबर की सुबह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तथाकथित शांति योजना को एक ही दिन में चार बार पूर्ण समर्थन दिया, जिस समर्थन की शुरुआत उन्होंने इजराइल और हमास द्वारा इस योजना के पहले चरण को मंजूरी दिये जाने के बाद एक ट्वीट से की और अंत में एक व्यक्तिगत बधाई फोन कॉल के साथ की। फिर शाम को उन्होंने 'एक्स' पर लिखा कि मैंने "मेरे मित्र" कहकर ट्रंप से बात की और *"ऐतिहासिक गजा शांति योजना की सफलता पर उन्हें बधाई दी"*। उन्होंने आशा व्यक्त की कि *"सभी संबंधित पक्ष राष्ट्रपति ट्रंप की पहल के पीछे एकजुट होंगे और लड़ाई खत्म करने व शांति सुनिश्चित करने के इस प्रयास का समर्थन करेंगे"*। इससे पहले, 30 सितंबर को मोदी ने ट्रंप द्वारा की गयी इस योजना की प्रारंभिक घोषणा का स्वागत किया था और इसे पश्चिम एशिया में स्थायी शांति के लिए एक ''व्यवहार्य मार्ग'' बताया था। फिर 4 अक्टूबर को उन्होंने गजा में शांति प्रयासों में निर्णायक प्रगति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति, जिसने हाल ही में भारतीय वस्तुओं पर 50% आयात शुल्क लगा दिया है, जिससे भारत का विदेशी व्यापार और अर्थव्यवस्था हिल गई है और पहलगाम आतंकी हत्याकाण्ड के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सशस्त्र संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनके द्वारा मध्यस्थता किये गए शांति समझौते को स्वीकार करने में भारत की अनिच्छा पर खुले तौर पर नाराजगी व्यक्त की, की प्रशंसा या यूं कहें कि उनकी घिनौनी चाटुकारिता की हद ही नहीं थी। यहां तक कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पिछले 25 सितंबर को एच-1बी वीजा के लिए मौजूदा शुल्क 2,000 डॉलर से बढ़ाकर 5,000 डॉलर प्रति वर्ष कर दिया है, जो कि चौंका देने वाला 1,00,000 डॉलर प्रति वर्ष है, जिसका अमेरिका में रोजगार पाने वाले भारतीय पेशेवरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसलिए यह दर्शाता है कि अमेरिका भारत के खिलाफ चाहे जो भी सख्त कदम उठाए, प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादी शासकों की नाराजगी मोल नहीं ले सकती, तो बेशर्मी से, शांतिप्रिय भारतीय नागरिकों की राय की उपेक्षा करते हुए और भारत की जनता के साम्राज्यवाद-विरोधी संघर्ष की गौरवशाली परंपरा का तिरस्कार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप के पक्ष में गीत गा रहे हैं, जिन्होंने गजा में सबसे भीषण नरसंहार को अंजाम देने के लिए जायोनी इजराइली शासन को कूटनीतिक और सैन्य, दोनों ही रूपों में लगातार समर्थन दिया है। एक राक्षस को शांतिदूत मानकर उसकी पूजा करना! ऐसा करने वाले का नाम है प्रधानमंत्री मोदी!

नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप तक ही अपनी बात सीमित नहीं रखी। उन्होंने कसाई और युद्ध अपराधी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की भी उनके ''मजबूत नेतृत्व'' के लिए प्रशंसा की। 'एक्स' पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा: ''हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। यह प्रधानमंत्री नेतन्याहू के मजबूत नेतृत्व का भी परिचायक है।'' प्रधानमंत्री मोदी का नेतन्याहू की सराहना वाला पोस्ट ऐसे समय में आया है, जब ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, आयरलैंड, स्पेन और नॉर्वे के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे कई पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीनी राज्य का समर्थन किया है।

प्रधानमंत्री ने इजरायली प्रधानमंत्री की प्रशंसा करते हुए यह भी दोहराया कि ''दुनिया में कहीं भी किसी भी रूप या अभिव्यक्ति में आतंकवाद अस्वीकार्य है।'' नेतन्याहू और ट्रंप के अलावा दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी भला और कौन हैं, जो हजारों निर्दोष, निहत्थे, भूख से त्रस्त नागरिकों, खासकर बच्चों का कत्लेआम करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। उन्होंने राहत केंद्रों पर भोजन और पानी पाने के लिए उमड़े भूखे गजावासियों पर गोलियां चलाने में भी संकोच नहीं किया। फिर प्रधानमंत्री मोदी, उनके कैबिनेट सहयोगियों और भाजपा नेताओं को क्या अधिकार है कि वे किसी की भी हत्या सहित किसी भी अपराध को अंजाम देने या उसमें शामिल होने के लिए आलोचना करें?

●○●

वेनेजुएला के खिलाफ युद्ध की साजिश रचने के अमेरिकी कदम की

एसयूसीआई (सी) ने की कड़ी निंदा

एसयूसीआई (कम्युनिस्टे) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 26 अक्तूबर 2025 को जारी प्रेस बयान में कहा:

"हम अमेरिकी साम्राज्यवादियों की घोषणा की कड़ी निंदा करते हैं कि वे ड्रग तस्करी वाली नावों के खिलाफ तथाकथित ऑपरेशन को तेज करने के नाम पर दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला के तटवर्ती जलक्षेत्र में 90 लड़ाकू विमानों को वहन करने में सक्षम दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत भेज रहे हैं। यह स्पष्ट रूप से वेनेजुएला के खिलाफ एक नए युद्ध की साजिश है, जहां सत्ता परिवर्तन करने के लिए एक से अधिक तख्तापलट के प्रयासों सहित उनकी तमाम कोशिशें अब तक नाकाम रही हैं। अमेरिकी शासकों की इस युद्ध साजिश की पुष्टि तब होती है, जब वेनेजुएला के एक विपक्षी नेता और अमेरिकी साम्राज्यवादियों के एक पिट्ठू लोपेज ने, जो 2020 से स्पेन में निर्वासन में है, सार्वजनिक रूप से देश पर अमेरिकी सैन्य आक्रमण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। अमेरिका लंबे समय से वेनेजुएला को डरा-धमकाकर अपने अधीन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिकी एकाधिकारी पूंजीपतियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राजनीतिक गतिविधियों में भारी निवेश किया है ताकि वहां उनकी कठपुतली सरकार कायम की जा सके और उस देश के विशाल तेल भंडार पर कब्जा किया जा सके। यह बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के एक शीर्ष सलाहकार ने स्वीकार की है।

सभी युद्ध-विरोधी शांति-पसंद लोगों को विरोध में उठ खड़े होना चाहिए और सैन्य शक्ति का उपयोग करके किसी देश की संप्रभुता को पैरों तले रौंदने की ट्रम्प प्रशासन की इस साजिश को नाकाम कर देना चाहिए।"

सीपीडीआरएस द्वारा एसआईआर के विरुद्ध वेबिनार

केन्द्र व राज्यों में सरकार चाहे किसी भी झंडे की हो, लोकतांत्रिक अधिकारों और धर्मनिरपेक्षता पर हमले बढ़ते जा रहे हैं। 21 सितंबर को कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमाक्रेटिक राइट्स एंड सेक्युलरिज्म (सीपीडीआरएस) ने चुनाव आयोग द्वारा कराये जा रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर एक महत्वपूर्ण अखिल भारतीय वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य भ्रम को दूर करना और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर स्पष्टता प्रदान करना था। इसमें 20 राज्यों से कई प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्होंने ऑनलाइन व्यक्तिगत और सामूहिक रूप में विभिन्न शहरों में प्रोजेक्टर स्क्रीनिंग के माध्यम से वेबिनार देखा।

वेबिनार को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त डॉ. एस.वाई. कुरैशी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता और सीपीडीआरएस के सलाहकार प्रशांत भूषण, सीपीडीआरएस के महासचिव प्रोफेसर कुंचे श्रीधर और प्रसिद्ध मानवाधिकार व नागरिक अधिकार कार्यकर्ता सीपीडीआरएस के सलाहकार द्वारिकानाथ रथ ने संबोधित किया।

केरल की आशा कार्यकर्ताओं पर पुलिस की क्रूर कार्रवाई की घटना की कड़ी निंदा

केरल की आशा कार्यकर्ताओं पर क्रूर पुलिस कार्रवाई की घटना की कड़ी निन्दा करते हुए एआईयूटीयूसी के महासचिव कॉमरेड शंकर दासगुप्ता ने 23 अक्टूबर, 2025 को जारी प्रेस बयान में कहा:

"ऑल इंडिया यूनाइटेड ट्रेड यूनियन सेंटर (एआईयूटीयूसी) की अखिल भारतीय कमेटी, तिरुवनंतपुरम में राज्य के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास, क्लिफ हाउस के सामने शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही केरल की आशा कार्यकर्ताओं पर की गई क्रूर पुलिस कार्रवाई की कड़ी निंदा करती है और इस बर्बरता के दोषी पुलिस अधिकारियों को कड़ी सजा देने की मांग करती है। केरल में लंबे समय से चल रहे आशा आंदोलन को दबाने के राज्य सरकार के फासीवादी रवैये की निंदा करते हुए एआईयूटीयूसी मांग करती है कि राज्य सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर केरल राज्य की आशा कार्यकर्ताओं की न्यायोचित मांगों को पूरा करने के लिए राज्य की आशा यूनियन के साथ सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत शुरू करे।"

केरल की आशा बहनों पर पुलिस जुल्म के विरोध में प्रदर्शन

रेवाड़ी (हरियाणा) : 27 अक्तूबर को यहां एआईयूटीयूसी से सम्बद्ध आशा कार्यकर्ता यूनियन हरियाणा (2074) ने जिला स्तरीय सभा की और अपनी मांगों के समर्थन मे प्रर्दशन करके मुख्यमंत्री, हरियाणा के नाम ज्ञापन भेजा। सभा में केरल की आशा कार्यकर्ताओं पर पुलिस बर्बरता के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया गया

रांची में छात्र रैली

रांची (झारखण्ड) : शिक्षा को पूर्ण पतन से बचाने के लिए छात्रों की विभिन्न जायज मांगों को लेकर झारखंड राज्य एआईडीएसओ द्वारा 19 अक्टूबर को यहां छात्रों की एक विशाल रैली आयोजित की गई।

Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Marutinandan Printers and Publishers, Shakti Complex,6/18, Sameypur Industrial Area, Delhi-110042 and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005.
Editor: Comrade Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C). **Phone No. : 9416763089, 9868350503** Email: **sarvaharadrishtikon@gmail.com**